VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS
+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS

(आज का विश्लेषण)

(04 July 2024)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- **SEBI ने हिंडेनबर्ग पर भारतीय कानून तोड़ने का आरोप लगाया**
- **स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक बढ़ाया गया**
- **MCQ**

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

SEBI ने हिंडेनबर्ग पर भारतीय कानून तोड़ने का आरोप लगाया:

मामला क्या है?

- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च, अमेरिका स्थित हेज फंड मैनेजर मार्क किंगडन और चार अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें उन पर अडानी समूह के खिलाफ शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए गैर-सार्वजनिक जानकारी का उपयोग करने के लिए मिलीभगत करने का आरोप लगाया गया है।
- कारण बताओ नोटिस के अनुसार किंगडन ने मॉरीशस स्थित एक फंड के माध्यम से गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने से पहले शॉर्ट पोजीशन स्थापित की, जिसके परिणामस्वरूप 150 अरब डॉलर का बाजार मूल्य खत्म हो गया।
- इसने कहा कि रिपोर्ट ने पाठकों को "गुमराह" किया और अडानी समूह के शेयरों में "घबराहट" पैदा की, "कीमतों को अधिकतम संभव सीमा तक कम किया और उसी से लाभ कमाया"।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या है?

- 24 जनवरी, 2023 (भारत में 25 जनवरी) को न्यूयॉर्क स्थित निवेशक शोध फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह पर "दशकों से खुलेआम स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग धोखाधड़ी योजना" का आरोप लगाते हुए 106 पन्नों की रिपोर्ट जारी की।
- यह रिपोर्ट अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के 20,000 करोड़ रुपये के फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (FPO) से पहले जारी की गई थी।
- इस रिपोर्ट जारी होने के बाद अडानी कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई और FPO को भी वापस ले लिया गया था हालांकि अडानी समूह ने सभी आरोपों से इनकार किया था।

सेबी का कारण बताओ नोटिस किस बारे में है?

- हिंडनबर्ग के अनुसार सेबी के नोटिस में कहा गया है कि हिंडनबर्ग ने अडानी लिमिटेड के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन बनाने और मुनाफा बुक करने के लिए गैर-सार्वजनिक जानकारी के अग्रिम ज्ञान का उपयोग करने के लिए कुछ संस्थाओं के साथ मिलीभगत की।

- नोटिस में हिंडनबर्ग रिसर्च, इसके संस्थापक नाथन एंडरसन, साझेदार-निवेशक मार्क किंगडन और किंगडन के स्वामित्व वाली या उसके नियंत्रण वाली तीन संस्थाओं का नाम लिया गया है।
- सेबी ने आरोप लगाया है कि 30 नवंबर, 2022 को शॉर्ट सेलर ने अडानी समूह पर अपनी रिपोर्ट का एक मसौदा विशेष रूप से अपने ग्राहक किंगडन कैपिटल मैनेजमेंट के साथ साझा किया था, जो बाद में प्रकाशित हिंडनबर्ग रिपोर्ट के समान ही था।
- सेबी के निष्कर्षों के अनुसार, किंगडन ने कथित तौर पर मई 2021 में हिंडनबर्ग के साथ शोधित प्रतिभूतियों में व्यापार से होने वाले मुनाफे का 30 प्रतिशत साझा करने के लिए एक समझौता किया था।
- कारण बताओ नोटिस में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यह अस्वीकरण कि उसने केवल गैर-भारतीय कारोबार वाली प्रतिभूतियों के माध्यम से ही पोजीशन बनाए रखी, भ्रामक थी, क्योंकि इसने किंगडन की पोजीशन से होने वाले मुनाफे में अपनी प्रत्यक्ष हिस्सेदारी को छुपाया था।

कोटक बैंक इस तस्वीर में कहां आता है?

- अपने बयान में, हिंडनबर्ग ने कहा कि सेबी के नोटिस में "भारत के सबसे बड़े बैंकों और ब्रोकर फर्मों में से एक कोटक बैंक का नाम स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है...जिसने हमारे निवेशक साझेदार [किंगडन] द्वारा अडानी के खिलाफ दांव लगाने के लिए इस्तेमाल किए गए ऑफशोर फंड ढांचे का निर्माण और देखरेख की थी।
- इसके बजाय, इसने केवल के-इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड का नाम लिया और 'कोटक' नाम को 'केएमआईएल' के संक्षिप्त नाम से छिपा दिया"।
- इसके जवाब में, कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा कि केआईओएफ एक सेबी-पंजीकृत एफपीआई है जिसे 2013 में स्थापित किया गया था, और जो ग्राहकों के संबंध में उचित केवाईसी प्रक्रियाओं का पालन करता है।

स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक बढ़ाया गया:

चर्चा में क्यों हैं?

- केंद्र सरकार ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के तहत स्मार्ट सिटी मिशन को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया है।
- जून 2015 में शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए एक प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया था।
- इस मिशन में देश के चयनित शहरों के भीतर के क्षेत्रों को एक क्षेत्र विकास योजना के आधार पर मॉडल क्षेत्रों के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है, जिसका शहर के अन्य हिस्सों और आस-पास के शहरों और कस्बों पर भी असर पड़ने की उम्मीद है।

स्मार्ट सिटी मिशन में अब तक क्या हुआ है?

- उल्लेखनीय है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 शहरों में लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपये की लागत से 8,000 से अधिक बहु-क्षेत्रीय परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं।

- 3 जुलाई तक 100 शहरों ने मिशन के तहत 7,188 प्रोजेक्ट (कुल प्रोजेक्ट का 90%) पूरे कर लिए हैं, जिनकी लागत ₹1,44,237 करोड़ है।
- 3 जुलाई को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि ₹19,926 करोड़ की लागत वाली शेष 830 परियोजनाएं भी पूरी होने के अंतिम चरण में हैं।

स्मार्ट सिटी मिशन को आगे क्यों बढ़ाया गया है?

- मिशन को कुछ राज्यों/शहर सरकार के प्रतिनिधियों से शेष 10% परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कुछ और समय देने के लिए कई अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। ये शेष चल रही परियोजनाएँ कार्यान्वयन के उन्नत चरण में हैं और विभिन्न जमीनी स्थितियों के कारण विलंबित हो गई हैं।
- इन अनुरोधों का संज्ञान लेते हुए, भारत सरकार ने इन शेष 10% परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मिशन अवधि को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया है।

स्मार्ट सिटी मिशन क्या है?

- स्मार्ट सिटी मिशन भारत के शहरी विकास में एक नया प्रयोग है। जून 2015 में अपनी शुरुआत के बाद से, मिशन ने कई नवीन विचारों को अमल में लाने का प्रयास किया है, जैसे कि 100 स्मार्ट शहरों के चयन के लिए शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा, हितधारकों द्वारा संचालित परियोजना चयन, कार्यान्वयन के लिए स्मार्ट

सिटी स्पेशल पर्पज व्हीकल्स का गठन, शहरी शासन में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल समाधानों का असरदार तरीके से इस्तेमाल आदि।

- 100 शहरों में से प्रत्येक ने परियोजनाओं का एक विविध सेट विकसित किया है, जिनमें से कई बहुत ही अनोखी हैं और पहली बार लागू की जा रही हैं।

स्मार्ट शहरों के केंद्र में सतत विकास:

- 27 सितंबर 2023 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM) के तहत शहरों, स्वच्छ जल और स्वच्छता, स्वच्छ ऊर्जा और आर्थिक विकास पर 70% से अधिक परियोजनाएँ संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, जबकि SCM परियोजनाओं ने 17 SDG में से 15 में एक या दूसरे तरीके से बड़े पैमाने पर योगदान दिया है, लगभग 44% SDG 11 के उद्देश्य के अनुरूप थे - शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना।

स्मार्ट सिटी मिशन की आवश्यकता क्यों है?

- भारत की वर्तमान जनसंख्या का लगभग 31% को शहरों में बसता है और इनका सकल घरेलू उत्पाद में 63% (जनगणना 2011) का योगदान हैं। ऐसी उम्मीद है

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

कि वर्ष 2030 तक शहरी क्षेत्रों में भारत की आबादी का 40% रहेगा और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 75% का होगा।

- इसके लिए भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के व्यापक विकास की आवश्यकता है। ये सभी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने एवं विकास एवं प्रगति के एक गुणी चक्र की स्थापना करने में महत्वपूर्ण हैं।

स्मार्ट सिटी की अवधारणा क्या है?

- स्मार्ट सिटी अपनी सबसे अहम जरूरतों एवं जीवन में सुधार करने के लिए सबसे बड़े अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- स्मार्ट सिटी मिशन के दृष्टिकोण में, उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देने का है जो मूल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएँ और अपने नागरिकों को एक सभ्य गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करें, एक स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण एवं 'स्मार्ट' समाधानों के प्रयोग का मौका दें।
- विशेष ध्यान टिकाऊ और समावेशी विकास पर है और एक रेप्लिकेबल मॉडल बनाने के लिए है जो ऐसे अन्य इच्छुक शहरों के लिए प्रकाश पुंज का काम करेगा।

- स्मार्ट सिटी मिशन के कोर बुनियादी सुविधाओं के तत्व:

  - पर्याप्त पानी की आपूर्ति
  - निश्चित विद्युत आपूर्ति
  - ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता
  - कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन
  - किफायती आवास, विशेष रूप से गरीबों के लिए
  - सुदृढ़ आई टी कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण
  - सुशासन, विशेष रूप से ई-गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी
  - टिकाऊ पर्यावरण
  - नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों की सुरक्षा, और
  - स्वास्थ्य और शिक्षा।

MCQ:

1. चर्चा में रहे अमेरिकी फर्म 'हिंडनबर्ग रिसर्च के अडानी समूह से जुड़े रिपोर्ट' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

   1. जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर "दशकों से खुलेआम स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग धोखाधड़ी योजना" का आरोप लगाया था।
   2. हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने के पीछे कोई व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना नहीं था, बल्कि सार्वजनिक हित था।

   उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   (a) केवल 1

   (b) केवल 2

   (c) 1 और 2 दोनों

   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

   Ans: (a)

2. हाल ही में चर्चा में रहे अडानी समूह मामले में 'हिंडनबर्ग रिसर्च' को नोटिस भेजने को लेकर चर्चा में रहे SEBI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) SEBI की स्थापना 12 अप्रैल, 1992 को की गयी थी।

(b) यह भारत में शेयर मार्केट को विनियमित करने की शीर्ष संस्था है।

(c) यह एक सांविधिक संस्था है।

(d) उपर्युक्त सभी कथन सही हैं।

Ans:(d)

3. चर्चा में रहे 'स्मार्ट सिटी मिशन' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. स्मार्ट सिटी मिशन भारत के शहरी विकास में एक नये प्रयोग के रूप में जून 2015 में शुरू किया गया था।

2. इस मिशन के तहत शहरों, स्वच्छ जल और स्वच्छता, स्वच्छ ऊर्जा और आर्थिक विकास पर 70% से अधिक परियोजनाएँ संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans:(c)

4. जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में शहरों का देश के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान है?

(a) 83 प्रतिशत

(b) 75 प्रतिशत

(c) 63 प्रतिशत

(d) 42 प्रतिशत

Ans:(c)

5. चर्चा में रहे 'स्मार्ट सिटी मिशन' के प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. आधिकारिक बयानों के अनुसार 3 जुलाई तक मिशन के तहत कुल परियोजनाओं का शत -प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है।

2. इसके तहत 100 शहरों में लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपये की लागत से 8,000 से अधिक बहु-क्षेत्रीय परियोजनाएं विकसित की जानी थी।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans: (b)